(d) Clearance of proposals is an ongoing process whith depends upon decision of the Liiikage Committee meetings held periodically after taking into account such factors as feasibility of linkage in consultation with coal companies, Mifnistry of Railways, Mtaistry of Power and Central Electricity Authority.

देश में कागज कारखाने

*274.**श्रीमती मालती शर्मा** :
प्रो. राम बख्श सिंह वर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कागज का उत्पादन करने वाले कारखाने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,:

(ख) देश में कागज की मांग और इसके उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या यह सच है कि देश में मांग के अनुपात में कागज का उत्पादन कम है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है, और

(ड.) कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)
(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान न कागज की मांग और उत्पादन निम्नानुसार है :-

	*मांग	उत्पादन
1994-95	25.85	25.10 लाख टनस
1995-96	27.78	27.10 लाख टनस
1996-97	30.28	27.96 लाख टनस

(ग) से (ड.) देश कागज के क्षेत्र में लगभग आत्म निर्भर है । कागज की घरेलु आपूर्ति उसकी मांग के साथ-साथ बढ़ रही है । कागज तथा कागज के बोर्डों की व्यापक एंव बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए घरेलु उद्योग पूरी तरह से सक्षम है । आयात नगण्य है और यह वर्ष 1996-97 में घरेलु मांग का लगभग 5% ही था : सरकार ने देश में कागज का उत्पादन/ उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्निलिखित कदम उठाये हैं :-

1. कागज उद्योग 17 जुलाई, 1997से पूर्णत : लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ।उद्यमियां को अब केवल औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.) के पास औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन वायर करना होता है ।

2. पूर्ण लाइसेंसमुक्तीकरण से औद्योगिक विकास में वृद्धि होने की आशा है और इस उद्यमियों को इन क्षेत्रों में निवेश एंव प्रौद्योगिकी संबधी निर्णय लेने में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान किये जाने से औद्योगिक विकास के उदारीकरण को और बल मिलेगा ।

3. प्रथम, 15,000 मी.टन वार्षिक उत्पादन पर 75 प्रतिशत से अधिक अपर-परागत कच्चे माल से बने कागज पर 5 प्रतिशत कम उत्पाद शुल्क प्रभारित किया जाता है।

4. चालू बजट में काष्ठ आधारित कागज तथा काष्ठ आधारित गत्ते पर उत्पादन शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है ।

5. कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कोयले और रसायनों के आयात पर सीमा शुल्क में पर्याप्त कमी की गई है ।

6. काष्ठ लठ्ठों और काष्ठ टुकड़ों के आयात पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है ।

*__स्त्रोत:__ लुग्दी एंव कागज उद्योग के लिए कार्य योजना समिति की रिपोर्ट 1996.

7.केन्द्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान ने, जोकि सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, कागज उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में रासायनिक प्रतिलाभ प्रणाली, कच्चे माल संबधी, अध्ययन और अन्य अभिनव परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, जिससे देश में कागज के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली है।

1991 में घोषित औद्योगिक उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप कागज इत्यादि का विनिर्माण करने हेतु 573 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दायर किये गये हैं, जिनकी प्रस्तावित क्षमता 95.48 लाख टन प्रतिवर्ष हैं

विवरण

क्रं.सं.	राज्य/संघशसितप्रदेशकानाम	कागज मिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	असम	4
3.	बिहार	9
4.	गुजरात	55
5.	हरियाणा	18
6.	हिमाचल प्रदेश	15
7.	जम्मू एंव कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	17
9.	केरल	4
10.	मध्य प्रदेश	18
11.	महाराष्ट्र	63
12.	नागालेंड	1
13.	उड़ीसा	8
14.	पंजाब	23
15.	राजस्थान	8
16.	तमिलनाडु	24
17.	उत्तर प्रदेश	68
18.	पश्चिम बंगाल	23
19.	चंडीगढ़	1
20.	पांडिचेरी	1
	कुल	380